STATEMENT BY MINISTER

Price Policy for Raw cotton for 1987-88 Season

THE MINISTER OF AGRICULTURE (SHRI G. S. DHILLON):

Sir,

1. After taking into account all relevant factors including the recommendations of the Commission for Agricultural Costs and Prices, Government have decided to fix the minimum support prices for the fair average quality of raw cotton for the 1987-88 season as follows:

(a) For the basic variety, H-4, in the long and superior long staple group of cotton, the minimum support price shall be Rs. 550 per quintal. The support prices for other varieties in this staple group will be fixed by the Textile Commissioner i nthe light of their normal market price differentials with the basic variety.

(b) For F-414|H-777 variety, the minimum support price shall be Rs. 440 per quintal. For varieties other than those in the long and superior long staple group, the Textile Commissioner will fix the support prices in the light of their normal market price differentials with F-414|H-777 variety.

2. The Cotton Corporation of India will undertake price support operations in all cotton growing States, except Maharashtra, in case market prices tend to fall below the level of the minimum support prices fixed by the Government.

3. The minimum support prices of raw cotton of fair average quality fixed by the Government for 1987-88 season mark an increase of Rs. 10.00 per quintal over the corresponding prices for the previous season and are intended to provide continued incentive to cotton growers to increase production and productivity of cotton.

4. In Maharashtra cotton will be purchased by the Maharashtra Cotton Federation.

Thank you.

श्री राम चन्द्र विकल (उत्तर प्रदेश) : उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि न्यूनतम समर्थन मूल्य और अधिकतम समर्थन मूल्य, इससे किसानों को क्या लाभ होगा? यह जो महाराष्ट्र को छोड़कर बाकी पर लागू होगा तो महाराष्ट्र को छोड़ने का कारण क्या है? तीसरा, मैं यह जानना चाहता हूं कि सूखे के कारण जिन किसानों की कपास पैदा ही नहीं हो सकी है, उस पर लागत तो आ गयी, फसल बोने पर लागत आ गई और फसल सूखे के कारण हुई ही नहीं तो उन किसानों को भी सहायता देने का क्या सरकार का विचार है?

श्री जी० एस० ढिल्लो : ड्राउट रिलीफ में जो हो सकेगा करेंगे, प्राइस फिक्सिंग में कुछ ज्यादा नहीं हो सकेगा। ड्राउट के बारे में जब आयेगा तब विचार किया जायेगा।

[**The Vice-Chairman (Shri H. Hanumanthappa)** in the Chair.]

SARDAR JAGJIT SINGH AURORA (Punjab): I find that the increase in price per quintal, as shown by the hon. Minister, comes to one paisa per seer or per kilo. I would like to know if any computation has been done to see what is the rise in prices of inputs this year as compared to last year. My second point is that the cotton crop this year in Punjab has been in the region of 15 lakh bales. In answer to one of my questions, it has been admitted that it was 13.6 lakh bales, but my information is that it is 15 lakh bales. Since it has been found that the present arrangements for buying cotton are inadequate, it had been suggested by me in one of the previous questions to see if special arrangements could be made to buy cotton in Punjab because, as it is, it is being sold much below the fixed price.

डा० बापू कालदाते (महाराष्ट्र) : उपसभाध्यक्ष महोदय, यह जो ब्यान मंत्री महोदय ने दिया है इसमें दो बातों की तरफ मैं आपका ध्यान अवश्य खींचना चाहता हूं। एक तो आप इस बात को जानते हैं कि महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य

[डा० बापू कालदाते]

है जिसने बिचौलियों को कम करने के लिये बहुत साल पहले से एकाधिकार कपास खरीद की योजना लागू की थी, क्योंकि आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि शोषण का जो माध्यम है वे ये बिचौलिये लोग हैं। कपास के क्षेत्र में किसानों को अधिक उत्तेजना मिले, उनको अधिक उत्साह मिले इसके लिये एक तरफ से हम बिचौलिये लोगों को कम करने का प्रयास करते रहे और दूसरी ओर महाराष्ट्र में इसकी विशेष अवस्था देखते हुए, उनकी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए जो सी० सी० आई० ने अपने न्यूनतम दाम का फैसला कर दिया, उससे कुछ ज्यादा ही, ताकि उनको इंसेंटिव मिले और वे कहीं बाहर जाकर बिचौलियों के हाथ में कपास न दें और महाराष्ट्र में सारा कपास इस तरह से इकट्ठा करें, इस दृष्टि से हम प्रयास करते थे। कुछ दिन पहले मुझे महाराष्ट्र के सहकारिता मंत्री का पत्र प्राप्त हुआ है, जिसका जिक्र मैंने किया था। लास्ट इयर, गये साल, महाराष्ट्र के किसानों को मोनोपली काटन परचेज के जरिये 612 रुपये प्रति क्विंटल मिलते थे। आपने उनको लिखा है कि अगर आप सी० सी० आई० के रेट्स से ज्यादा दाम देने का प्रयास करेंगे तो हम आपकी मदद नहीं कर सकते हैं। आज इस समय महाराष्ट्र की सरकार इस बात पर बाध्य हो गई है कि वह हमारे किसानों को बजाय 612 के इस समय 540 रुपये दे रही है एक तरफ उनको लगने वाली सारी चीजें जिनका सरदार जी ने जिक्र किया जैसे इनपुट्स है, खाद का सवाल है, बिजली के दाम का सवाल है, डीजल का सवाल है, औजारों की कीमतों का सवाल है, अपनी मेहनत का सवाल है, जहां-जहां न्यनतम मजदूरी दी गई है, खेती में आने वाली लागत के दाम बढ़ते जा रहे हैं साथ ही साथ पिछले साल जब 612 रुपये मिलते थे अब उसको 540 रुपये दिय जाए तो क्या आप नहीं समझते हैं कि उनके मन में यह भावना पैदा नहीं होगी कि केन्द्रीय सरकार किसानों की मदद करने के बजाये नीचा दिखाने के लिए शोषण करने के लिए बिचौलिये का काम कर रही है। यह भावना महाराष्ट्र में बहुत हद तक इतनी गहराई से किसानों में आ गई है जिसका परिणाम महाराष्ट्र की सरकार तथा हम लोग जब वहां जाते हैं तो हम महसूस करते हैं। मैं तो तीन चीजें मंत्री जी से पूछना चाहता हूं। आपने जो इस साल दाम तय किये हैं क्या उस में खेती में लगने वाली चीजों के दाम, मुनाफे का प्रतिशत ध्यान में रख कर किये हैं। आपने जो एक क्विंटल का दाम तय किया तो क्या इस में यह ध्यान भी रखा है कि किसानों को दो-तीन-चार परसेंट मुनाफा भी मिलना चाहिये ताकि उसको खेती में ज्यादा पैदावार करने की प्रेरणा मिले। एक तो आपने उसको लागत के आधार पर दाम नहीं दिया है और नम्बर दो महाराष्ट्र के किसानों को आपके आदेश के कारण जो क्षति पहुंची है उसके लिए आप सहानुभूति-पूर्वक विचार करके महाराष्ट्र सरकार को यह इजाजत जरूर दीजिये ताकि महाराष्ट्र में किसानों को पिछले साल जितना मिलता था कम से कम उतना इस साल भी मिले। आपका आदेश किसानों की लूट का साधन न बने इस दिशा में केन्द्रीय सरकार क्या करना चाहती है, यह मैं जानना चाहता हूं।

श्री बी० सत्यनारायण रेड्डी: उप-सभाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने कपास के उत्पादक किसानों को कुछ रियायतें देने के संबंध में जो बयान दिया है, मैं यह जानना चाहूंगा कि कपास उत्पादन करने वाले किसान जो पिछड़े इलाकों में रहते हैं उनके बारे में क्या सरकार की कोई ऐसी नीति है जिसके तहत उनको ज्यादा सहुलियतें दी जाऐ ज्यादा इनसेंटिव दिये जाऐं? क्या ऐसी कोई नीति सरकार ने बनाई है? अगर ऐसी नीति बनाई है तो वे कौन-कौन से इलाके हैं जिनको सरकार ने इस संबंध में लिया है? दूसरी बात मैं यह जानना चाहता हू कि जो प्राइस उन्होंने तय किये हैं वह इस बयान के असार दो किस्म के हैं एक सुपी-

रियर लांग स्टेपल ग्रुप आफ काटन के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस 540 रुपय प्रति क्विंटल और दूसरा एफ-414 एच-777 वरायटी है उसका 440 रुपये प्रति क्विंटल तय किया है। मैं यह जानना चाहता हूं कि इसकी जो रेश्या है आन दी होल 1 रुपये प्रति क्विंटल का इज़ाफा आपने किया है। इस चीज का हर साल काटन के संबंध में एक रुपया, दो रुपया, इस तरीके से आप बढ़ाते जा रहे हैं, जब आप फ़ी क्विंटल इज़ाफा करने के लिए तय करते हैं तो यह किस आधार पर करते हैं, किस आधार पर आप यह निर्णय करते हैं ? क्या इसका निर्णय करने से पहले जो उत्पादन करने वाले लोग हैं किसान हैं जो कपास पैदा करने वाले हैं उनसे राय वगैरह भी लेते हैं, क्या उनसे यह भी पूछते हैं कि उनको प्रति क्विंटल उत्पादन करने में कितना खर्च पड़ता है, कितना मुनाफा मिलता है, इन तमाम चीजों के बारे में क्या सरकार ने सोचा है और क्या यह सब कुछ सोचने के बाद इस निर्णय पर पहुंचे हैं, यह बताने की कृपा करें ?

श्री शंकर सिंह बाघला (गुजरात) : ऐसा लगता है कि सरकार घोड़े भाग जाने के बाद तबेलों पर ताला लगाने पर तुली है। कई राज्यों में कपास तो निकल गया, किसान मर रहा है और किसानों का मज़ाक करने के लिए हमारे मंत्री जी ने एक स्टेटमेंट दिया जिसका कोई मतलब नहीं है . . . (व्यवधान) अभी भी काटन का चल रहा है 1987, अभी की बात कर रहा हूं। वे किसान जो मर गये उनके लिए आपके पास कौन सी योजना है, जिनका आज तक लास हुआ है। आप सी० सी० आई० की बात कर रहे हैं। क्या सी० सी० आई० आपके कंट्रोल में है ? 1986-87 में सी० सी० आई० ने कौन से राज्य में किस भाव से कितना काटन परचेज किया इसके लिए फिगर्स दीजिए और महाराष्ट्र को अलग रखने का मतलब ह यह भी आप बताइए।

SHRI G. S. DHILLON: Mr. Vice-Chairman, Sir, after laying the Price Policy Statement, for Raw Cotton for 1987-88 Season, so many hon. Members have asked different questions which very often have been discused in this House either in the debate or in answers to the various questions. General Aurora has asked about the basis for determining the price. I would like to tell him that the Agricultural Costs and Prices including inter alia cost of production and terms of trade etc. Commission settles that on the basis of a number of relevant factors and not on the lowest denomination.

As far as the fixation of price is concerned, a number of times, this matter comes up in the House on each occasion. I have stated various factors determining the prices that are always taken into account by the Commision for Agricultural Costs and Prices and we normally accept the prices as determined by them. When they fix a price, they consult State Governments, they consult various organizations and expert bodies and they have the costs on the basis of surveys conducted by Agriculture Universities. They consult farmers also. Besides that, they examine the cost of production, and they take into account, changes is the prices of inputs fertilizers, pesticides, implements, family labour, hired labour and so many other factors. (*Interruption*) They take into account the cost of production changes in input costs, parity between different crops, impact on overall price situation and terms of trade was also included. What the farmers receive and what the farmers spend, that is also into consideration and after taking into account all these factors, they determine the prices.

There are experts, Now, as I told in the other House, there was one farmers representative and three official experts and besides that, the Chairman, that is 4:1 I have now laid down a plan and already the Cabinet has approved that plan that the Chairman will be an outstanding agricultural economist and against three official experts, we will have now three farmers representatives. The little bit of doubt one had in the beginning was perhaps the farmers, opinion was in minority and the others in majority. That doubt stands eliminated now. And I do hope with this new

[Shri G. S. Dhillon]

policy and this new structure of the Costs Commission, there will be some fresh thinking. But whatever it be, stand by determination of prices fixed by them on the basis of guidelines laid down before them. As for Maharashtra, the Federation got the cotton direct from the growers at the prices determined by the State and distributed it with a small share by themselves. The result was that the Federation was suffering heavey losses. That is the reason why we have now fixed one standard set of prices for the country as a whole. When the Federation was offering higher prices in Maharashtra even the neighbouring territories, even the neighbouring States, brought their produce to these centres and the rseult was a little unbalancing factor in other States whereas the minimum support price in other parts of the country was as set by Central Government. So, to remove this disparity and to finish the losses suffered by the Federation we had to go in for this. We will monitor this and later on, if need be, we will again come before the House as to what results have flowed from this policy.

SARDAR JAGJIT SINGH AURORA: We still do not know what the difference was between the input last year and the input this year. That was the question that was asked. The Agriculture Ministry should know what the difference was. And that question still remains unanswered.

SHRI G. S. DHILLION: You do not know. I am a farmer myself. None is worse hit than myself. I have been a cotton grower also. (*Interruption*) There was glut of cotton, there was overproduction, last year, and we had no market to go to. It was only in the month of November that the prices picked up. We have decided to go in for exports of six lakh bales. The result is prices started picking up and now they are much higher than the minimum support price fixed by the Commission. I did not know that you would ask this question; otherwise, I would have brought the actual figures as to what is the disparity between the prices fixed by the Commission and the actual prices prevailing in the market. That was higher. It was only for a while that the burden was on the minimum price support. Internationally the prices have gone much higher and a time may come when we will have to have two prices, from our textile industry and also from the exporters. There was no scarcity of cotton. Because of the glut we had to keep a level. But thinking that next time there will be more demand and production may go down because of the glut last time, we have increased this price so that, if need be, if the demand for exports rises, we may not fall short.

MOTION OF THANKS ON THE PRESIDENT'S ADDRESS—Contd.

SHRI VALAMPURI JOHN (Tamil Nadu): Mr. Vice-Chairman, at the very outset I would like to say that the President's Address is a catalogue of achievements, real as well as imaginary. It is a package of pious platitudes and I must say, admittedly, there is one cardinal feature, there is one fundamental fact, that the entire Address of the President is dotted with a lot of references to communal problems and the very Address itself ends with a very optimistic note that we will fight communalism tooth and nail. But I would like to say, while we appreciate the Government's efforts to fight the Frankenstein monster of communalism, while we are one with the Government in trying to wipe out the hydra-headed monstrosity of communalism in this country. We do appreciate that there are vested interests in this country which are trying to set, which are setting, one community against another and which are dividing the whole nation, the whole national fabric, into warring principalities in the name of religion, in the name of caste and in the name of community. While we do appreciate that there are people who are interested in dividing this country on communal lines, I would only like to request the Government to do a sort of soul-searching for itself and see whether it has not contributed in the past to the same communal frenzy. I will quote only two examples for want of time. What has happened in U.P.? You speak of the three-language formula. But here if it is the three-language formula, if the